

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 621वीं बैठक दिनांक 20/02/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 7917/2020 M/s Pushpa Enterprises, Prop. Shri Anand Tamrakar, G-7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Dist. Bhopal, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (20000 cum per annum) (Khasra No. 1540/1), Village - Padwaar, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) (Old Name) M/s Anandeshwar Agro Foods Pvt. Ltd, Shri Ravindra Singh Bundela, Taldarwaza, Dist. Tikamgarh, MP**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1540/1), Village - Padwaar, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 6.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 468वीं दिनांक 16/12/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । सिया की 742वीं बैठक दिनांक 18/8/22 में हुए निर्णय अनुसार टॉर में सेर्स पुष्पा इंटरप्राइजेस, भोपाल के नाम से पत्र क्रमांक 1452 दिनांक 26/8/22 के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान केन नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

अनुसार खदान के कुछ भाग में पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा तथा आवंटित कुल 6.00 हे. क्षेत्र में से खनन मात्र 3.50 हे. में अनुमोदित खनन योजना अनुसार किया जायेगा, जिसका विवरण प्रस्तुतीकरण में दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-73 के सरल क्रमांक-07 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-1,08,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 20,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्षेत्र व गहराई के आधार पर इस खदान का माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-1,08,000 घनमीटर हैं तथा अनुमोदित माइन प्लान के अनुसार केवल रेत प्राप्ति की मात्रा 20,000 घनमीटर दर्शाई गई है, जो उपलब्ध मात्रा से काफी कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के पूर्व इस जिले का टेंडर संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो गई थी, जिस कारण मात्रा में अंतर आ रहा है। समिति की अनुशंसा है कि इस स्थिति में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई मात्रा का पुनः निर्धारण जिला खनिज अधिकारी द्वारा किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार खनिज विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत मात्रा 20,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक का उत्पादन इस खदान से न हो, जिस हेतु मॉनिटरिंग संबंधी विशेष व्यवस्थायें स्थापित की जाये।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिमी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा ग्राम में पेयजल की व्यवस्था, रोजगार, गांव की सड़क से रेत का परिवहन नहीं तथा सिद्धेश्वर मंदिर की बाउंड्रीवाल का निर्माण इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई. आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 20,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 18.08 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.74 लाख प्रति वर्ष।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 09.30 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	6200
2	पड़वार, बरवा, और निधौली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, सीताफल,, नींबू, अचार, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
योग			7,200

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पड़वार के सरपंच की राय से दो हैंड पंप की स्थापना कराई जायेगी	80,000 / -
सब्जी उत्पादन हेतु बढ़ावा	10,000 / -
सिद्धेश्वर मंदिर के बाउंड्री वाल के निर्माण में सम्पूर्ण बालू निःशुल्क दिया जायेगा	-
योग	90,000 / -

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

2. **Case No 7976/2020 M/s Pushpa Enterprises, Prop. Shri Anand Tamrakar, G-7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 10.0 ha. (80,000 cum per annum) (Khasra No. 2531/13), Village - Goyra, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) (Old Name) M/s Anandeshwar Agro Foods Pvt. Ltd, Shri Ravindra Singh Bundela, Taldarwaza, Dist. Tikamgarh,**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2531/13), Village - Goyra, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 10.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 471वीं दिनांक 05/01/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया की 742वीं बैठक दिनांक 18/8/22 में हुए निर्णय अनुसार टॉर भी मेंसर्स पुष्पा इंटरप्राइजेस, भोपाल के नाम से पत्र क्रमांक 1456 दिनांक 26/8/22 के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 20/02/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेंसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ. प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान केन नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के उत्तरीय-पूर्वी भाग में पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा तथा आवंटित कुल 10.00 हे. क्षेत्र में से खनन मात्र 6.00 हे. में अनुमोदित खनन योजना अनुसार किया जायेगा, जिसका विवरण प्रस्तुतीकरण में दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-75 के सरल क्रमांक-18 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-1,80,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 80,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्षेत्र व गहराई के आधार पर इस खदान का माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-1,80,000 घनमीटर हैं तथा अनुमोदित माइन प्लॉन के अनुसार केवल रेत प्राप्ति की मात्रा 80,000 घनमीटर दर्शाई गई है, जो उपलब्ध मात्रा से काफी कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के पूर्व इस जिले का टेंडर संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो गई थी, जिस कारण मात्रा में अंतर आ रहा है। समिति की अनुशंसा है कि इस स्थिति में जिला सर्वेक्षण

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

रिपोर्ट में दी गई मात्रा का पुनः निर्धारण जिला खनिज अधिकारी द्वारा किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार खनिज विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत मात्रा 80,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक का उत्पादन इस खदान से न हो, जिस हेतु मॉनिटरिंग संबंधी विशेष व्यवस्थायें स्थापित की जाये।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिणी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा ग्राम में पेयजल की व्यवस्था, रोजगार, गांव की सड़क से रेत का परिवहन नहीं इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 80,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 24.04 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.55 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 14.92 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	9950
2	गोयरा, व कंडेला के शासकीय विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा,, अशोक, नीम, कनक चंपा, मौलश्री, परीजात गुलमोहर इत्यादि।	50
3	खानपुर, मौगिरवां और चक रसुला नंबर 1 गांवों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, सीताफल, नींबू, अचार, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
योग			12,000

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
परियोजना प्रस्तावक के माध्यम से ग्राम पंचायत को 60 हजार रुपये दिये जाएंगे, जिससे पशुओं के लिए गौशाला विकसित करने में सहयोग मिलेगा।	60,000 / -
गाँव गोयरा, के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर प्रिंटर के साथ वितरण किया जायेगा।	50,000 / -
ओरछा वन्य प्राणी अभ्यारण में वन्य प्राणी रहवास एवं रखरखाव पर	50,000 / -
योग	1,60,000 / -

3. **Case No 7903/2020 M/s Pushpa Enterprises, Prop. Shri Anand Tamrakar, G-7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.20 ha. (70000 cum per annum) (Khasra No. 332), Village - Dhaurara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) (Old Name) M/s Anandeshwar Agro Foods Pvt. Ltd, Shri Ravindra Singh Bundela, Taldarwaza, Dist. Tikamgarh.**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 3321), Village - Dhaurara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 5.20 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 467वीं दिनांक 02/12/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया की 742वीं बैठक दिनांक 18/8/22 में हुए निर्णय अनुसार टॉर भी मेंसर्स पुष्पा इंटरप्राइजेस, भोपाल के नाम से पत्र क्रमांक 1456 दिनांक 26/8/22 के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 20/02/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ. प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान केन नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के लगभग 60 प्रतिशत से अधिक भाग में पानी भरा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुरानी गूगल इमेज है तथा वर्तमान स्थिति में आवंटित खनन क्षेत्र में रेत उपलब्ध है, जिसके फोटोग्राफ प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी से भी जानकारी प्राप्त की गई है तथा संबंधित खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 399 दिनांक 20/02/23 के माध्यम से अवगत कराया है कि स्वीकृत रेत खदान में अप्रैल माह से मई माह तक जल भराव कम हो जाता है, जिससे खदान में उत्खनन कार्य किया जा सकता है, जिसकी प्रति प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न की गई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कुल उपलब्ध क्षेत्र 5.20 हे. में से 2.80 हे. क्षेत्र में पानी भरा हुआ है तथा 2.40 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध है जिसमें से 70,000 घनमीटर / वर्ष रेत का उत्पादन किया जा सकता है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पुनरीक्षित विवरण प्रस्तुतीकरण में दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-75 के सरल क्रमांक-20 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-93,600 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 70,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिमी भाग से किया जायेगा। स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

द्वारा रोजगार, वृक्षारोपण एवं धूल के कारण फसले खराब इत्यादि सुझाव/आपत्ति प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 70,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 17.43 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.86 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 07.78 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	5190
2	धरौरा ,के प्राथमिक विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा,, अशोक, नीम, कनक-चंपा, मौलश्री, परीजात गुलमोहर इत्यादि।	50
3	धरौरा गाँव में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, सीताफल, नींबू, अचार, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
योग			6240

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम धरौरा के प्राथमिक विद्यालय में एक हैंडपंप की स्थापना कराई जायेगी।	50,000 /—
ग्राम धरौरा के प्राथमिक विद्यालय में एक हैंडपंप की स्थापना कराई जायेगी।	रु 50,000 /—
गाँव धरौरा के खदान स्थल के पास दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए ग्राम पंचायत समिति को योगदान	रु 50,000 /—
ओरछा वन्य प्राणी अभ्यारण में वन्य प्राणी रहवास एवं रखरखाव पर	50,000 /—
योग	2,00,000

4. Case No 9606/2023 M/s. Euphoria Mines and Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, District-Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Banjari Sand Quarry on Ken River in an area of 12.30 ha. (55,000 Cum per annum) (Khasra No. 730), Village-Banjari, Tehsil-Chandla, District-Chhatrapur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 730), Village-Banjari, Tehsil-Chandla, District-Chhatrapur (MP) 12.30 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2540 दिनांक 23/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है एवं इस खदान का स्वयं का कुल क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत केन नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र केन नदी पर है तथा प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के अधिकांश भाग में पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वह रेत निकलने के कारण ऐसा दिख रहा है तथा तथा पूर्व की गूगल इमेज देखने पर यह स्पष्ट होता है कि आवंटित खनन क्षेत्र में रेत उपलब्ध है। परियोजना

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

प्रस्तावक ने बताया कि इस वर्ष वर्षा अच्छी होने के कारण पर्याप्त मात्रा में रेत उपलब्ध है फिर भी खदान का वह भाग जिसमें पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेक फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-76 के सरल क्रमांक-25 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-2,21,400 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 55,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
5. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
7. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
12. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये।
13. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
14. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।
15. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें।

5. Case No 9609/2023 M/s. Euphoria Mines and Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, District-Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Lasgarha Sand Quarry on Ken River in an area of 12.60 ha. (50000 Cum per annum) (Khasra No. 405), Village-Lasgarha, Tehsil-Chandla, District-Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 405), Village-Lasgarha, Tehsil-Chandla, District-

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

Chhatarpur (MP) 12.60 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2555 दिनांक 23/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 5.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत केन नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में 210 मीटर पर पुल है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र केन नदी पर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के अधिकांश भाग में पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वह रेत निकलने के कारण ऐसा दिख रहा है तथा तथा पूर्व की गूगल इमेज देखने पर यह स्पष्ट होता है कि आवंटित खनन क्षेत्र में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस वर्ष वर्षा अच्छी होने के कारण पर्याप्त मात्रा में रेत उपलब्ध है फिर भी खदान का वह भाग जिसमें पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-75 के सरल क्रमांक-24 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल (60 प्रतिशत)-2,26,800 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 50,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में 220 मीटर पर पुल है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
5. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
8. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. चूंकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

14. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
15. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
16. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा । परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

6. Case No. - 9628/2023 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Lessee, R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Dhigsara Sand Mining Project in an area of 5.7750 ha. (90,436.5 Cum per annum) (Khasra No. 29/1), Village-Dhigsara, Tehsil-Saikheda, District-Narsinghpur (MP).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. - 29/1), Village-Dhigsara, Tehsil-Saikheda, District-Narsinghpur (MP) 5.7750 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार डॉ जतिन श्रीवास्तव, मेसर्स पी एंड एम सल्यूशन, नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 795 दिनांक 19/09/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह रेत खदान दूधी नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. -78 के सरल क्रमांक-2.10 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-1,45,530 मैट्रिक टन (1,03,950 घनमीटर) उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 90,436.5 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। तथा टॉर 90,436.5 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टैण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक पलोरा एण्ड फाउना स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
13. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

7. Case No 9629/2023 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Lessee, R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Maheshwar Sand Mining Project in an area of 10.00 ha. (1,62,000 Cum per annum) (Khasra No. 124), Village-Maheshwar, Tehsil-Saikheda, District-Narsinghpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 124), Village-Maheshwar, Tehsil-Saikheda, District-Narsinghpur (MP) 10.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार डॉ जतिन श्रीवास्तव, मेसर्स पी एंड एम सल्यूशन, नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 802 दिनांक 19/09/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 5.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह खदान दूधी नदी पर स्थित है जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसंधान खदान के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में नदी प्रवाह का है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग से नदी का प्रवाह है, वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-78 के सरल क्रमांक - 2.3 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-2,52,000 मैट्रिक टन (1,80,000 घनमी.) उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1,62,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक प्लोरा एण्ड फाउना स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

13. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगे। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें।

8. Case No 9630/2023 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Lessee, R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Arjungaon Sand Mining in an area of 6.00 ha. (97,200 Cum per annum) (Khasra No. 128, 187), Village-Arjungaon, Tehsil-Gadarwara, District-Narsinghpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 128, 187), Village-Arjungaon, Tehsil-Gadarwara, District-Narsinghpur (MP) 6.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार डॉ जतिन श्रीवास्तव, मेसर्स पी एंड एम सल्यूशन, नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 792 दिनांक 19/09/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित हैं एवं इस खदान का क्षेत्रफल 5.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह दूधी नदी पर स्थित है जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में लगभग 650 मीटर की दूरी पर 02 रेलवे के ब्रिज हैं, अतः इनकी संरक्षण योजना (रेलवे विभाग के रिकार्ड अनुसार स्पॉन के आधार पर गणना कर) प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-2.13 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-1,51,200 मैट्रिक टन (लगभग 1,08,000 घनमीटर) उल्लेखित है तथा टॉर 97,200 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में लगभग 650 मीटर की दूरी पर 02 रेलवे के ब्रिज हैं, अतः इनकी संरक्षण योजना (रेलवे विभाग के रिकार्ड अनुसार स्पॉन के आधार पर गणना कर) ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरा एण्ड फाउना स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
7. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फाउना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
14. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा । परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

9. Case No 9652/2023 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Lessee, R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Tumda Sand Quarry in an area of 10.00 ha. (1,62,000 Cum per annum) (Khasra No. 670), Village-Tumda, Tehsil-Saikheda, District-Narsinghpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 670), Village-Tumda, Tehsil-Saikheda, District-Narsinghpur (MP) 10.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार डॉ जतिन श्रीवास्तव, मेसर्स पी एंड एम सल्यूशन, नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 800 दिनांक 19/09/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 5.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह दूधी नदी पर स्थित है जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-2.4 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-2,52,000 मैट्रिक टन (लगभग 1,80,000 घनमीटर) उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा टॉर 1,62,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी फ्लोरा एण्ड फाउना स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंपोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

4. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फाउना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
13. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा । परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

10. Case No 9649/2023 M/s. Euphoria Mines and Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, District-Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Harrai Sand Quarry on Ken River in an area of 12.50 ha. (65,000 Cum per annum) (Khasra No. 277/1), Village- Harrai, Tehsil-Chandla, District-Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 277/1), Village- Harrai, Tehsil-Chandla, District-Chhatarpur (MP) 08.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

आज दिनांक 20/02/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र.उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2555 दिनांक 23/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित हैं एवं इस खदान का क्षेत्रफल 5.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान केन नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का कुछ भाग में नदी का पानी है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है, वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-77 के सरल क्रमांक-26 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-2,25,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 65,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र उत्तरप्रदेश की सीमा के अंदर रहा है जो संभव नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक इस स्थिति में खनन क्षेत्र की लोकेशन सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट से सत्यापित कर जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी प्लोरा एण्ड फाउना स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

5. गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र उत्तरप्रदेश की सीमा के अंदर रहा है जो संभव नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक इस स्थिति में खनन क्षेत्र की लोकेशन सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट से सत्यापित कर जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सैंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
8. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फाउना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
14. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

11. Case No 9644/2023 M/s. Euphoria Mines and Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, District-Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Ghatpipariya-3 Sand Quarry on Narmada River in an area of 08.00 ha. (1,28,949 Cum per annum) (Khasra No. 306), Village-Ghatpipariya-3, Tehsil-Baraily, District-Raisen (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 306), Village- Ghatpipariya-3, Tehsil-Baraily, District-Raisen (MP) 08.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

आज दिनांक 20/02/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह, मे0. ए सीरीज इंवारेटेक इंडिया प्रा. लि. नोएडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 428 दिनांक 31/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित हैं एवं इस खदान का क्षेत्रफल 5.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है तथा खनन मैनुअली किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-05 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-1,44,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 1,28,949 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टैण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरा एण्ड फाउना स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

8. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फाउना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
9. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।
13. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें।

12. Case No 9674/2023 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Lessee, R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad MP)-461775. Prior Environment Clearance for Murgakheda Sand Quarry (Narmada River) in an area of 5.00 ha. (81000 Cum per annum) (Khasra No. 206/2, 209/2, 211/2, 212/2, 213/2, 220/2, 223/2, 224/2, 227/2, 270/2, 271/2, 272/2, 272/1), Village-Murgakheda, Tehsil-Narsinghpur, District-Narsinghpur (MP)

This is case of River Sand Quarry on Narmada River. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra No. 206/2, 209/2, 211/2, 212/2, 213/2, 220/2, 223/2, 224/2, 227/2, 270/2, 271/2, 272/2, 272/1), Village-Murgakheda, Tehsil-Narsinghpur, District-Narsinghpur (MP), Area -5.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 769 दिनांक 19/09/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान कार्यरत नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम तथा उनके पर्यावरण सलाहकार श्री किशन शर्मा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया द्वारा अनुमोदित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है जिसकी तालिका-14 (पेज नं.-78) के सरल क्रमांक-1.8 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-1,26,000 मैट्रिक टन (लगभग 90,000 घनमीटर) उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 81,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तरीय भाग से किया जायेगा। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नदी के उत्तरीय भाग में स्वीकृत है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही खनन प्रस्तावित हैं तथा खनन मैनुअली किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिमी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 81,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.78 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.88 लाख प्रति वर्ष।
3. प्रस्तावित खनन कार्य नर्मदा नदी में होने कारण सिर्फ मैनुअली किया जाये।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 07.75 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
6. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में 2- बेड एवं 2- व्हीलचेयर की व्यवस्था	65,000
ग्राम मुर्गा खेड़ा कला में दो पंखे 10 शेयर 25 बेंच एवं बच्चों के खेलने हेतु खेलकूद की सामग्री दी जाएगी	35,000
कुल योग	1,00,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 02 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3500
2	परिवहन मार्ग (पौधों की ऊंचाई 1 मीटर)	खमेर, चिरोल, साजा, सप्तपर्णी, अचार, करंज, जंगल जलेबी, कदम, एवं अन्य प्रजातियाँ	500
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत मुर्गाखेड़ा)	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, अचार, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
कुल			6000

13. Case No 9570/2023 M/s Pushpa Enterprises, Prop. Shri Anand Tamrakar, G-7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)-462016 Prior Environment Clearance for Pipaliya Khurd Richawar Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (88200 cum per annum) (Khasra No. 256), Village-Pipaliya Khurd Richawar, Tehsil-Deori, District-Raisen (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 256), Village-Pipaliya Khurd Richawar, Tehsil-Deori, District-Raisen (MP) 5.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र.

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 427 दिनांक 31/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है तथा खनन मैनुअली किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-53 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल-90,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 88,200 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 88,200 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नदी के उत्तरीय भाग में स्वीकृत है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंशिक क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा खनन क्षेत्र का वह भाग जो आंशिक रूप से नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा परिवहन उत्तरीय दिशा से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 88,200 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 21.65 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.41 लाख प्रति वर्ष।
3. प्रस्तावित खनन कार्य नर्मदा नदी में होने कारण सिर्फ मैनुअली किया जाये।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 08.70 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियों चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

6. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	आवांटीत लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया-इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	कटग बांस, नागर मोथा, खस, खमेर, करंज, जामुन, कहवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5800
2	ग्राम पिपलिया खुर्द के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम मुनगा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	200
कुल			6,000

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के हेवीटाट डेवलपमेंट और स्टॉफ वेलफेयर के लिए ।	1,00,000 / —

14. Case No 9607/2023 M/s Pushpa Enterprises, Prop. Shri Anand Tamrakar, G-7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)-462016 Prior Environment Clearance for Barla Sand Quarry in an area of 0.330 ha. (5821 cum per annum) (Khasra No. 30), Village-Barla, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 30), Village-Barla, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP) 0.330 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 424

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

दिनांक 16/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 60 दिनांक 09/01/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित इन 03 (बारला, बेरखेड़ीघाट एवं तिलापुर) खदानों का रकबा 01 हे. से कम है यह व्यापारिक खदानें हैं, जिन पर न्यूनतम क्षेत्र के नियम लागू नहीं होते हैं। इस खदान का अनुमोदित माइन प्लान एवं अनुमोदित जिला सर्वेक्षण में अक्षांश-देशांश में भिन्नता है, जिसके संदर्भ में जिला खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 1081 दिनांक 15/09/2022 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिला सर्वेक्षण के अक्षांश-देशांश को मान्य किया जाता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बेतवा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है जिसमें रेत का परिवहन खेतों वाले रास्तों से किया जाये, जिससे कि सड़के क्षतिग्रस्त न हो तथा ग्राम पंचायत को आवश्यक होने पर ग्राम पंचायत रेत प्राप्त कर सकेगी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-51 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-5940 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5821 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 5821 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नदी के पूर्ण भाग में स्वीकृत है तथा आवंटित खनन क्षेत्र के मध्य भाग से होकर नदी का प्रवाह है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 5821 घनमीटर/वर्ष होने के कारण नदी में डूबे भाग को छोड़कर जिस भाग में रेत उपलब्ध है, वहाँ से रेत निकाली जा सकती है जिसमें 0.198 हे. में खनन कार्य किया जायेगा, जिसका विवरण प्रस्तुतीकरण में दिया गया है, जिसके अनुसार 5940 घनमीटर/वर्ष रेत उपलब्ध है जो स्वीकृत मात्रा 5812 घनमीटर/वर्ष ज्यादा है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 5821 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.65 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.73 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 0.75 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	500
कुल			500

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
रातापानी वाइल्ड लाइफ सैक्चुररी के हेवीटाट डेवलपमेंट और स्टॉफ वेलफेयर के लिए	50,000 / -

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

15. Case No 9608/2023 M/s Pushpa Enterprises, Prop. Shri Anand Tamrakar, G-7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)-462016 Prior Environment Clearance for Berkhedhi Ghat Sand Quarry in an area of 0.770 ha. (13582 cum per annum) (Khasra No. 72), Village-Berkhedhi, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP) [289559]

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No.72), Village-Berkhedhi Ghat, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP) 0.770_Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 928 दिनांक 16/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 60 दिनांक 09/01/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित इन 03 (बारला, बेरखेड़ीघाट एवं तिलापुर) खदानों का रकबा 01 हे. से कम है यह व्यापारिक खदानें हैं, जिन पर न्यूनतम क्षेत्र के नियम लागू नहीं होते हैं। इस खदान का अनुमोदित माइन प्लान एवं अनुमोदित जिला सर्वेक्षण में अक्षांश-देशांश में भिन्नता है, जिसके संदर्भ में जिला खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 1081 दिनांक 15/09/2022 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिला सर्वेक्षण के अक्षांश-देशांश को मान्य किया जाता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बेतवा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-49 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल-13,860 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 13,582 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 13,582 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नदी के पश्चिमी भाग में स्वीकृत है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा खनन क्षेत्र का वह भाग जो आंशिक रूप से नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा परिवहन भी पश्चिम दिशा से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्व भाग से एक मौसमी नाला मिल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मौसमी नाला पूर्वी भाग से मिल रहा है जबकि आवंटित खनन क्षेत्र नदी के पश्चिमी भाग में है तथा नदी के बहाव के विपरीत दिशा में 50 मीटर दूरी पर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 13,582 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.50 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.07 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 01.50 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयं वृक्षों की प्रजातियाँ चयनित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	अमलतास, मुनगा, कटहल, नीबू, अमरुद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	200
कुल			1200

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हेवीटाट डेवलपमेंट और स्टॉफ वेलफेयर के लिए	50,000 / -

16. Case No 9635/2023 M/s Pushpa Enterprises, Prop. Shri Anand Tamrakar, G-7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)-462016 Prior Environment Clearance for Tijalpur Sand Quarry in an area of 0.400 ha. (7056 cum Total production) (Khasra No. 123), Village-Tijalpur, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 123), Village-Tijalpur, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP) 0.400 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 922 दिनांक 16/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 60 दिनांक 09/01/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित इन 03 (बारला, बेरखेड़ीघाट एवं तिलापुर) खदानों का रकबा 01 हे. से कम है यह व्यापारिक खदानें हैं, जिन पर न्यूनतम क्षेत्र के नियम लागू नहीं होते हैं। इस खदान का अनुमोदित माइन प्लान एवं अनुमोदित जिला सर्वेक्षण में अक्षांश-देशांश में भिन्नता है, जिसके संदर्भ में जिला खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 1081 दिनांक 15/09/2022 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिला सर्वेक्षण के अक्षांश-देशांश को मान्य किया जाता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बेतवा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-50 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-7200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7056 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 7056 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नदी के पश्चिम भाग में आवंटित है तथा परिवहन भी पश्चिमी भाग से किया जायेगा।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 7056 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.65 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.55 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय। विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 0.75 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	500
कुल			500

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हेवीटाट डेवलपमेंट और स्टॉफ वेलफेयर के लिए	50,000 /—

17. Case No 9653/2023 M/s Pushpa Enterprises, Prop. Shri Anand Tamrakar, G-7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)-462016 Prior Environment Clearance for Singarpur Khodu Bharu Sand Mine in an area of 1.00 ha. (12000 Cum per annum) (Khasra No. 64/5), Village-Singarpur, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP)

This is case of Khodu Bharu Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 64/5), Village-Singarpur, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1862 दिनांक 02/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह खोदू भरु प्रकृति की खदान है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-04 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 120 मीटर पर तथा उत्तर दिशा में 95 मीटर पर नदी है, पूर्व दिशा में 85 मीटर कच्चा रोड़ तथा दक्षिण-पूर्व दिशा में 130 मीटर पर आबादी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र में 10 पेड़ लगे हैं किंतु प्रकरण खोदू-भरु का होने के कारण कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि खनन क्षेत्र के जिस भाग में पेड़ लगे हैं, उसे नॉन माईनिंग जोन घोषित किया गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-115 के सरल क्रमांक-04 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें रेत का अनुमानित भण्डार-12000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 12,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.50 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.64 लाख प्रति वर्ष।
3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
2	परिवहन मार्ग	आम, कटहल, खम्हेरए नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	200
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	200
कुल			1200

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम सिगारपुर के शासकीय प्राथमिक शाला में 1 कम्प्यूटर, प्रिन्टर, टेबल के साथ और 1 आलमारी लाइब्रेरी के लिये	60,000

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

18. Case No 9658/2023 Shri Himanshu Meena, Partner, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, District-Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Kadari Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (12000 Cum per annum) (Khasra No. 672), Village-Kadari, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 672), Village-Kadari, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP) 1.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1868 दिनांक 02/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. कम है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बुरहा नाला में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-48 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-27,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बुरहा नाला के पूरे भाग में स्वीकृत की गई है, जिसका लगभग 75 प्रतिशत भाग जल में डूबा हुआ है तथा आवंटित खनन क्षेत्र में एक चेकडेम भी बना है, अतः इसके दोनो ओर सेफजोन – नॉन माईनिंग के रूप में छोड़ा जाना चाहिए तथा परियोजना प्रस्तावक उचित संरक्षण योजना पुनरीक्षित सरफेस मैप के साथ प्रस्तुत करें। समिति की यह भी अनुशंसा है कि संबंधित खनिज अधिकारी से यह जानकारी भी प्राप्त की जाये कि चेकडेम के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में यदि पानी भरा है तो खनन किस प्रकार संभव होगा।

19. Case No 9647/2023 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Prop. R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Dighori Sand Quarry (On Dudhi River) in an area of 4.00 ha. (64800 Cum per annum) (Khasra No. 195), Village- Dighori, Tehsil-Gadarwara, District-Narsinghpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 195), Village- Dighori, Tehsil-Gadarwara,

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

District-Narsinghpur (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री किशन शर्मा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 788 दिनांक 19/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सीतारेवा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है (परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि त्रुटिवश एकल प्रमाण पत्र में नदी का नाम दूधी नदी लिखा गया है जबकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट व गूगल इमेज अनुसार नदी का नाम सीतारेवा नदी है)। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित क्षेत्र के कुछ भाग में नदी का प्रवाह है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी के प्रवाह वाले भाग में खनन नहीं किया जायेगा तथा कुल आवंटित क्षेत्र के 60 प्रतिशत भाग में खनन कार्य प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण प्रस्तुतीकरण में दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-79 के सरल क्रमांक-3.1 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-1,00,800 मैट्रिक टन (लगभग 72,000 घनमीटर) उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 64,800 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 64,800 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नदी के दक्षिण-पश्चिम भाग में आवंटित है तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा खनन क्षेत्र का वह भाग जो नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा खनन कार्य पश्चिमी भाग में उपलब्ध भाग से किया जायेगा और वही से परिवहन किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -64,800 मी³ प्रति वर्ष।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.14 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.67 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय। विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 06.07 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	2050
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत दिघोरी एवं जनपद पंचायत बाबई चीचली)	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, सीताफल, नींबू, अचार, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2000
2	परिवहन मार्ग (पौधों की ऊंचाई 1 मीटर)	खमेर, चिरोल, साजा, सप्तपर्णी, करंज, जंगल जलेबी, कदम, एवं अन्य प्रजातियां	750
कुल			4800

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु.में)
नौरादेही अभ्यारण में वन्य प्राणियों के रहवास एवं संरक्षण हेतु	50,000

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

ग्राम दिघोरी के प्राथमिक शाला में कुर्सी 10, बेंच एवं बच्चों के खेलने हेतु खेलकूद के सामान की व्यवस्था	40,000
ग्राम दिघोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक स्ट्रेचर बेड एवं सामान्य जरूरी चिकित्सीय उपकरण जैसे शुगर, बीपी, वजन नापने की मशीन की व्यवस्था।	35,000
कुल योग	1,25,000

20. Case No 9648/2023 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Prop. R/o Nehru Ward No. 13, Near Alka Talkies, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Bagdara Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (64800 Cum per annum) (Khasra No. 272), Village-Bagdara, Tehsil-Saikheda, District-Narsinghpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 272), Village-Bagdara, Tehsil-Saikheda, District-Narsinghpur (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 20/02/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री किशन शर्मा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 782 दिनांक 19/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान शक्कर नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-79 के सरल क्रमांक-4.3 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेण्शियल-1,00,800 मैट्रिक टन (लगभग 72,000 घनमीटर) उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 64,800 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 64,800 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नदी के उत्तर-पूर्वी भाग में स्वीकृत है, जिसके मध्य भाग से नदी की धारा का प्रवाह है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा आवंटित खनन क्षेत्र का वह भाग जिसमें जल प्रवाह हो रहा है, वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जावेगा। समिति ने पाया कि मार्च, 2022 की गूगल इमेज में आवंटित खनन क्षेत्र से

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

नदी प्रवाहित हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक खदान का वह भाग जहाँ से नदी प्रवाहित हो रही है, उसे नॉन माईनिंग के रूप में छोड़ते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण में पूर्व से ही आवंटित खनन क्षेत्र का वह भाग जहाँ से नदी की धारा प्रवाहित हो रही है उसे नॉन माईनिंग के रूप में छोड़ा गया है। पुनरीक्षित सरफेस मेप अनुसार आवंटित कुल क्षेत्र 4.0 हे. में से लगभग 2.50 हे. क्षेत्र को नॉन माईनिंग के रूप में छोड़ा गया है तथा खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र 1.50 हे. है, जिसमें 3.0 मीटर की गहराई के साथ 45,000 घन मीटर रेत निकाली जा सकती है अतः हमको पर्यावरण अभिस्वीकृति 64,800 घन मीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर 45,000 घन मीटर प्रतिवर्ष दी जाना उचित होगा तथा खनन कार्य पश्चिमी भाग में उपलब्ध भाग से किया जायेगा और वही से परिवहन किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति ने गूगल इमेज के अवलोकन से यह भी पाया कि संबंधित खनन अधिकारी द्वारा खनन हेतु उपलब्ध पोटेंशियल माईनिंग एरिया में लीज स्वीकृत नहीं की गई तथा जिस भाग में पानी है, उस भाग में लीज स्वीकृत की गई है। तत्संदर्भ में सिया स्तर से एक सुझाव पत्र खनिकर्म एवं भौमिक विभाग को जारी किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -45,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.14 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.67 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय। विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 06.07 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2500
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत दिघोरी एवं जनपद पंचायत बाबई चीचली)	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, सीताफल, नींबू, अचार, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1800
2	परिवहन मार्ग (पौधों की ऊँचाई 1 मीटर)	खमेर, चिरोल, साजा, सप्तपर्णी, अचार, करंज, जंगल जलेबी, कदम, एवं अन्य प्रजातियाँ	500
कुल			4800

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु.में)
नौरादेही अभ्यारण में वन्य प्राणियों के रहवास एवं संरक्षण हेतु	50,000
प्राथमिक विद्यालय बगदरा की मरम्मत, पुताई एवं विद्यालय में 20 बेंच एवं बच्चों के खेलने हेतु खेलकूद के सामान की व्यवस्था	50,000
कुल योग	1,00,000

21. Case No 9428/2022 M/s Sharma Associates, Authorized Person Shri Dinesh Sen, Devri Rajmarg, District Narsinghpur (MP)-487330, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (45000 Cum per year) (Khasra No. 415), Village - Dharampura, Tehsil - Shahpura, Dist. Jabalpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 415), Village - Dharampura, Tehsil - Shahpura, Dist. Jabalpur (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

प्रकरण सेक की पूर्व की 609वीं बैठक दिनांक 07/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश सेन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1597 दिनांक 24/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जबलपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-59 के सरल क्रमांक-20 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल-54,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 45,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 45,000 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान का आंशिक भाग नदी के जल में डूबा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा खनन क्षेत्र का वह भाग जो नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऐरिया मैप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग लगभग 220 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडेड एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 1597 दिनांक 24/05/2022 वन क्षेत्र 250 मीटर के अंदर नहीं है। उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशंसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 220 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इस स्थिति स्पष्ट करने बावत् पत्र लिखा जाये।

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 20/02/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश सेन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र.उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक ने उनके द्वारा संभागीय स्तर से गठित समिति की बैठक दिनांक 19/01/23 में अनुमति प्राप्त कर ली गई है तथा 2000 पौधों का रोपण नदी तट पर प्रथम वर्ष में ही (माह जून, 2023 के पहले) किया जायेगा तथा उनके देख-भाल हेतु राशि ग्राम पंचायत में जमा की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 45,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.62 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.00 लाख प्रति वर्ष।
3. प्रस्तावित खनन कार्य नर्मदा नदी में होने कारण सिर्फ मेन्यूअली किया जाये।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय। विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 05.10 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
6. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति- कटंग बांस	3400

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2023

		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा, डेंचा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	ग्राम धरमपुरा के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	200
कुल			3600

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
तहसील— शाहपुरा के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में 02 बेड गद्दे व वेडशीट के साथ एवं दो स्टील की बेच ।	50,000 /—
ग्राम पंचायत को पौधों के रखरखाव के लिए धनराशि ।	1,00,000 /—
योग	1,50,000 /.

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 20 फरवरी, 2023

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 20 फरवरी, 2023

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 20 फरवरी, 2023

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 20 फरवरी, 2023

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

- an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
 29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
 33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

35. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
36. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
37. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
38. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिपल जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

621वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2023

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।